आदर्श आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां

18वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा इसके गंभीर उल्लंघन के कारण आदर्श आचार संहिता ने एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। राजनीतिक दल इस संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि इसे शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सभ्य चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा तैयार किया गया था। हालाँकि, चूंकि भारत में चुनाव कोई रोक-टोक वाला युद्ध नहीं है, इसलिए यह आम सहमति अक्सर टूट जाती है और पार्टी नेता अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं खोते हैं।आखिरकार, चुनाव सभी के लिए नि:शुल्क हैं ऐसे में विकृतियां, स्पष्ट झूठ, शरारती गलत व्याख्याएं, गाली-गलौज - ये सभी के लिए एक पाठ्यक्रम के समान हैं।

संविधान ईसीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का आदेश देता है। दरअसल, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है। भारत के चुनाव आयोग बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1993) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की भूमिका और शक्तियों को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया: ईसीआई एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण है जिस पर कार्य और कर्तव्य का आरोप लगाया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करना। इसके पास संवैधानिक उद्देश्य और प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए सभी आकस्मिक और सहायक शक्तियाँ हैं। आयोग की शक्तियों की प्रचुरता उसके द्वारा निभाए जाने वाले उच्च संवैधानिक कार्यों से मेल खाती है।

प्रमुख प्रावधान:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों और चुनावी प्रक्रिया शुद्ध रहे, आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई थी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, समान अवसर एक आवश्यक शर्त है। संहिता के मुख्य प्रावधान हैं: कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या सांप्रदायिक घृणा पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों, समुदायों - धार्मिक या भाषाई - के बीच तनाव पैदा कर सकता है; अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगी। अन्य पार्टियों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी; वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जाएगी; कोई भी पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं होगा या अपराध नहीं करेगा।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन निर्देशों का उल्लंघन संहिता का गंभीर उल्लंघन है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखना असंभव हो जाता है। इसलिए, यह ईसीआई का कर्तव्य है कि वह उन उल्लंघनों की शीघ्र जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करे ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे। यहां सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है।

निवारक कार्रवाई पर:

यह सामान्य ज्ञान है कि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इसलिए, संहिता के उल्लंघन के लिए अदालत से कोई राहत लेना संभव नहीं है। पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र रास्ता आयोग से शिकायत करना और उसके हस्तक्षेप की मांग करना है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और न ही चुनाव आचरण नियम आदर्श आचार संहिता के लिए कोई प्रावधान करते हैं। हालाँकि, 1968 में म्ब् द्वारा लाए गए चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने का प्रावधान करता है। प्रतीक आदेश अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16 ए में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता या आयोग के अन्य निर्देश या आदेशों के उल्लंघन के मामले में, यह किसी पार्टी की मान्यता को निलंबित कर सकता है। , या, चरम स्थिति में, इसकी मान्यता भी वापस ले लें। किसी पार्टी की मान्यता निलंबित करने या वापस लेने से उसे उसके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह से वंचित कर दिया जाएगा। इससे एक मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए भारी समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी क्योंकि वह चुनाव में अपने आरक्षित प्रतीक का उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए, ईसीआई के पास आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की शक्ति है। हमने ईसीआई को उल्लंघन करने वालों को 24 से 48 घंटों के लिए चुनाव अभियान से हटाते देखा है। यह उल्लंघनकर्ता को चुनाव प्रचार से हटा भी सकता है, चाहे वह पार्टी में कितना भी बड़ा पद पर क्यों न हो। ईसीआई की ऐसी कार्रवाइयां निश्चित रूप से एक निवारक के रूप में काम करेंगी और राजनीतिक दलों को सही संदेश देंगी।

हालाँकि, अनुभव से पता चलता है कि दिवंगत टीएन शेषन के बाद, ईसीआई ने कभी भी इतनी निर्णायक कार्रवाई नहीं की, जितनी वह किया करते थे। टीएन शेषन ने राजनेताओं के मन में दहशत पैदा कर दी. भारत में चुनाव आज करो या मरो की लड़ाई है और यहां एकमात्र लक्ष्य दुश्मन को हराना है। राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन माना जाता है और लक्ष्य उन्हें खत्म करना है। चुनाव लंबे समय से सभ्य लोकतांत्रिक अभ्यास नहीं रह गए हैं, जहां प्रत्येक खिलाड़ी ईमानदारी से कानून द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करता है। अब, पुरुषों में निम्नतम भावनाओं को भड़काने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। एक समय राजनेताओं के बीच इस बात पर आम सहमति थी कि समाज में विशेष रूप से धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में धर्म एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग समाज को विभाजित करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। संविधान के निर्माताओं ने बुद्धिमानी से संविधान के ताने-बाने के रूप में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को चुना। उनका मानना था कि केवल धर्मनिरपेक्षता ही अपार विविधताओं वाले इस देश को एक साथ रख सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ने किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी अपील को एक भ्रष्ट आचरण बना दिया है जो चुनाव को अमान्य कर देगा। इस प्रकार, कानून द्वारा धर्म को चुनावी लड़ाई से बाहर रखा गया है। लेकिन राजनेताओं द्वारा इसे वापस लाकर इस युद्धक्षेत्र के केंद्र में स्थापित कर दिया गया है। देश चाहता है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से संबोधित करे।

शपथ का उल्लंघन:

चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सांप्रदायिक रूप से आरोपित भाषण देने के मुद्दे को ईसीआई या अदालतों द्वारा सख्ती से नहीं निपटाया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे व्यक्तियों के भाषण, जिनमें किसी विशेष धर्म या समुदाय या जाति के अनुयायियों के लिए बेहद जहरीले संदर्भ होते हैं और जो मतदाताओं के एक वर्ग में नफरत को बढ़ावा दे सकते हैं, मंत्री के रूप में ली गई शपथ का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। एक मंत्री, अपनी शपथ के माध्यम से, देश के लोगों को एक गंभीर आश्वासन देता है कि वह बिना पक्षपात या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के साथ सही काम करेगा। समाज के किसी वर्ग के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोलकर वे उनके प्रति अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रह और दुर्भावना को प्रदर्शित करते हैं जो शपथ का उल्लंघन है। संविधान या चुनाव कानून में मंत्रियों द्वारा शपथ का उल्लंघन करने पर कोई सजा निर्धारित नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 में धर्म के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम सजा के रूप में तीन साल की सजा का प्रावधान है। संघ के साथ-साथ राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्य उच्च संवैधानिक पद पर हैं और किसी के प्रति दुर्भावना के बिना सभी के लिए सही काम करने के लिए शपथ लेते हैं। इसलिए, इसके विपरीत उनकी ओर से किसी भी बयान से गंभीरता से निपटने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ईसीआई को ऐसे अवसर आने पर जन प्रतिनिधित्व अधि नियम 1951 की धारा 125 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का स्थायी निर्देश दे सकती है और मौजूदा चुनाव खत्म होने तक उल्लंघनकर्ताओं को अभियान से हटा भी सकती है।

शीर्ष अदालत ने हमेशा चुनाव की शुचिता बनाए रखने पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है: "चुनाव की शुचिता का क्या मतलब है? हमारे अनुसार, इसका मतलब यह है कि चुनाव न केवल भ्रष्ट आचरण से मुक्त होने चाहिए, बल्कि बुरे आचरण से भी मुक्त होने चाहिए" (ए. नीलालोहितदासन नादर बनाम जॉर्ज मैस्करीन)। धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर लोगों के दो वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देना एक बुरी प्रथा है। संविधान ईसीआई के हाथों में बहुत सारी शक्तियां देता है। आवश्यकता पड़ने पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : चुनाव में आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये सांविधिक दर्जे की होती हैं।
2. चुनाव तारीखों की घोंषणा के साथ ही यह लागू हो जाती है।
3. इसके उल्लंघन से संबंधित विवाद चुनाव आयोग की सलाह पर उच्च न्यायालय में निर्धारित किये जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

Que. Consider the following statements with reference to Model Code of Conduct in Elections:

1. These are of statutory status.
2. It comes into force as soon as the election dates are announced.
3. Disputes related to its violation are decided in the High Court on the advice of the Election Commission.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 3 only
(b) Only 2
(c) 2 and 3 only
(d) All of the above

उत्तर : B

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में आदर्श आचार संहिता की चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका चर्चा कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।